(क) क्या महाराष्ट्र कच्चा कपास (वसूली, प्रसंस्करण और विपणन) अधिनियम, 1971 की समय अवधि बढ़ाये जाने को आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव पर अब कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रफीक आलम) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।]

औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए बैंक ऋण

1644. **श्री राम नरेश यादव :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को ऋण प्रदान किए जाने को प्रोत्साहित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों में (1985, 1987 एवं 1988) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र में अलग-अलग कितनी-कितनी धनराशि ऋण के रूप में दी गई है ; और

(ग) इन वर्षों में दोनों क्षेत्रों से अलग-अलग कितना-कितना धन ऋण के भुगतान के रूप में वापस लिया गया है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अन्यों के साथ-साथ, कृषि, कुटीर और ग्राम उद्योग, लघु उद्योग, छः वाहनों तक सड़क परिवहन, लघु व्यापार, व्यवसायी और स्व-रोजगार प्राप्त व्यक्ति शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसचित जन जातियों को 5,000/- रुपये तक आवास ऋण, 500 रुपये तक का उपभोग ऋण शामिल है । सरकारी क्षेत्र के बकों द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों में निरंतर वृद्धि हो रही है ।

(ख) दिनांक 31 दिसम्बर, 1985, 1986 और 1987 को कृषि और उद्योग क्षेत्र के नाम अग्रिमों की बकाया राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(राशि करोड़ रुपए)

	1985	1986	1987
कृषि उद्योग	8660	10166	11693
1. बड़े और मझौले उद्योग	14575	17161	19597
2. लघु क्षेत्र के उद्योग	7450	8723	10241

(ग) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से लघु उद्योग क्षेत्र से संबंधित ऋणों की वापसी अदायगी के बारे में सूचना प्राप्त नहीं होती है । अलबत्ता, जून, 1986 और जून, 1987 (अद्यतन उपलब्ध) की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंको के प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की वसूली की स्थिति नीचे दी गयी है :—

(राशि करोड़ रुपए)

वर्ष	मांग	वसूली	मांग की तुलना में वसूली की प्रतिशतता
1986	3911	2211	56.6
1987	4468	2551	57.1